

भारत पर FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट

प्रारंभिक परीक्षा:

[वित्तीय कार्रवाई कार्य बल](#), [रतन और आभूषण नरियात संवर्द्धन परिषद](#), [जन धन-आधार-मोबाइल \(JAM\) पहल](#), [वस्तु एवं सेवा कर](#), [राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण](#), [इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट](#), [प्रवर्तन नदिशालय](#)

मुख्य परीक्षा:

अवैध वित्त, धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में भारत की प्रगति

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वित्तीय कार्रवाई कार्य बल \(FATF\)](#) ने भारत पर अपनी [पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट](#) जारी की, जिसमें अवैध वित्त से निपटने में देश की महत्त्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया।

- **नोट:** जून 2024 में सियापुर में आयोजित FATF प्लेनरी ने भारत के लिये पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया, जिसमें कहा गया कि उसने वैश्विक धन शोधन निगरानी संस्था की आवश्यकताओं के साथ "उच्च स्तर का तकनीकी अनुपालन" हासिल किया है।
- FATF ने भारत को "नियमिती अनुवर्त्ती" श्रेणी में रखा है, जो FATF द्वारा दी गई सर्वोच्च रेटिंग श्रेणी है और इस प्रकार यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत [संघीय ढाँचे](#) वाला एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया।
- भारत के अतिरिक्त ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ही ऐसे [जी-20 देश हैं जिन्हें इस श्रेणी में रखा गया है।](#)

भारत पर FATF पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- **सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र:** भारत तीन क्षेत्रों में आंशिक रूप से अनुपालन करता पाया गया।
 - गैर-लाभकारी संगठन (NPO): धर्मार्थ संगठनों के रूप में पंजीकृत और [कर छूट](#) का लाभ उठाने वाले NPO [आतंकवादी वित्तपोषण के प्रति संवेदनशील](#) हो सकते हैं।
 - इन संगठनों से संबंधित जोखिमों से निपटने के लिये प्रणाली को बेहतर उपायों की आवश्यकता है।
- **राजनीतिक पकड़ वाले लोग (PEP):** घरेलू PEP के लिये धन के स्रोत, धन के स्रोत और लाभकारी स्वामित्व के बारे में अस्पष्टता मौजूद है। सरकार को इन अस्पष्टताओं को दूर करने की आवश्यकता है।
- **नामिती गैर-वित्तीय व्यवसायों और पेशा (DNFBP):** DNFBP के वनियमन और पर्यवेक्षण में खामियाँ मौजूद हैं, विशेष रूप से धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के संबंध में।
 - DNFBP भारत के [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसमें बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों का योगदान 7% तथा रयिल एस्टेट का योगदान 5% है।
- **धन शोधन संबंधी जोखिम:** भारत में अवैध गतिविधियाँ धन शोधन संबंधी जोखिम के प्राथमिक स्रोत हैं, जिसमें धोखाधड़ी, [साइबर धोखाधड़ी](#), [भ्रष्टाचार](#) और [मादक पदार्थों की तस्करी](#) शामिल हैं।
- **PMS मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति संवेदनशील:** बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों (PMS) का उपयोग स्वामित्व का कोई नशान छोड़े बिना [बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरण करने के लिये किया जा सकता है।](#)
- **भारत के PMS बाजार का आकार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के प्रति इसकी संवेदनशीलता में योगदान देता है। इस क्षेत्र में लगभग 1,75,000 डीलर शामिल हैं, लेकिन केवल 9,500 ही [रतन और आभूषण नरियात संवर्द्धन परिषद \(GJEPC\)](#) के साथ पंजीकृत हैं।**
 - FATF की रिपोर्ट में कहा गया है कि PMS क्षेत्र में [सीमा पार](#) से संचालित आपराधिक नेटवर्क की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा न्यूनतम जाँच की जा सकती है।
 - पर्यवेक्षण हरे और रतनों के एक प्रमुख उपभोक्ता और उत्पादक के रूप में भारत की वैश्विक भूमिका को देखते हुए, धन शोधन संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिये [धोखाधड़ी और तस्करी तकनीकों पर नरितर निगरानी रखने की आवश्यकता है।](#)
- सोने और हीरे की तस्करी से संबंधित ML/TF जोखिमों पर बेहतर जोखिम की समझ और गहन गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता

है।

- **आतंकवादी वित्तपोषण का संकट:** भारत को गंभीर आतंकवादी संकटों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से [सेइसलामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट \(ISIL\)](#) और [अल-कायदा](#) से संबंधित समूहों से, जो जम्मू एवं कश्मीर में और उसके आसपास सक्रिय हैं।
 - **पूर्वोत्तर में कश्मीरीय विद्रोह** और **वामपंथी उग्रवादी समूह** भी आतंकवाद का संकट उत्पन्न करते हैं।
 - यद्यपि देश **आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम और उसे बाधित करने पर बल देता है, फरि भी** अभियोजन को समाप्त करने और आतंकवादी वित्तपोषणकर्त्ताओं को दोषी ठहराने के लिये और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।
- **वित्तीय समावेशन:** भारत ने **वित्तीय समावेशन को काफी हद तक बढ़ाया है, बैंक खाताधारकों की संख्या में** तीव्र वृद्धि हुई है और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग में वृद्धि हुई है।
 - छोटे खातों के लिये सरलीकृत प्रक्रिया से वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है जिसने AML/CFT के प्रयासों में योगदान दिया है।
 - डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये **जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) पहल की** सराहना की गई।
 - **आपूर्ति शृंखला पारदर्शिता बढ़ाने के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST)**, ई-चालान और ई-बिलि के कार्यान्वयन की सराहना की गई।
- **आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध कार्रवाई:** **राष्ट्रीय अनुवेषण अभिकरण (NIA)** और **प्रवर्तन नदिशालय** द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की सराहना की गई।
- **FATF की सफारिशें:**
 - **लंबित मुकदमे:** भारत को **लंबित धन शोधन** के मुकदमों को शीघ्र नपिटाने तथा **मानव तस्करी** और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से नपिटने की अपनी प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **लक्षित वित्तीय प्रतर्बंध:** भारत को बिना किसी वलिंब के धन और परसिंपत्तियों को फ्रीज करने के लिये अपने ढाँचे में सुधार करना चाहिये तथा प्रतर्बंधों के संबंध में संचार को सुव्यवस्थित करना चाहिये।
- **घरेलू PEP:** भारत को अपने धन शोधन वरिधी कानूनों के तहत **घरेलू PEP** को परभाषित करने और उनके लिये जोखिम-आधारित उन्नत उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

भारत के लिये FATF के पारस्परिक मूल्यांकन के क्या नहितार्थ हैं?

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और परसिंपत्त विसूली:** FATF से भारत को मली मान्यता से वजिय माल्या और नीरव मोदी जैसे **भगोडे आर्थिक अपराधियों** से संबंधित अवैध परसिंपत्तियों का पता लगाने और विसूली में अन्य देशों के साथ सहयोग करने की इसकी क्षमता में वृद्धि होती है।
- **वैश्विक वित्तीय नगिरानी संस्थाओं के साथ बेहतर सहयोग से आतंकवाद के वित्तपोषण वरिधी प्रयासों में सहायता मिलती है।**
- **वैश्विक वित्तीय प्रणालियों तक बेहतर पहुँच:** FATF रेटिंग से वैश्विक वित्तीय बाजारों तक भारत की पहुँच में सुधार होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना और नविश करना आसान हो जाएगा।
- यह मान्यता भारत के **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** के वैश्विक वसितार का समर्थन करती है, जिससे यह **सीमा पार डिजिटल भुगतान** के लिये पसंदीदा विकल्प बन जाता है।
- **नविशकों का वशिवास सुदृढ़ करना:** सकारात्मक मूल्यांकन **भारत की वशि्वसनीयता बढ़ाता है** और वित्तीय बाजारों में **वदिशी नविशकों का वशिवास बढ़ाता है, जिससे भारत प्रत्यक्ष वदिशी नविश (FDI)** के लिये अधिक आकर्षक गंतव्य बन जाता है।

//



वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF)

परिचय

- * ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का निगरानीकर्ता

स्थापना:

- * जुलाई 1989, पेरिस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान

उद्देश्य:

- * मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का विरोध करना।

सदस्य:

- * 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपियन कमीशन व खाड़ी सहयोग परिषद)
- * इंडोनेशिया एक पर्यवेक्षक देश है।

मुख्यालय:

- * सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित

ग्रेलिस्ट होने के परिणाम:

- * FATF (IMF, World Bank, ADB) से संबद्ध वित्तीय संस्थानों से आर्थिक प्रतिबंध
- * वित्तीय संस्थानों और देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या
- * अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी
- * अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार

भारत और FATF:

- * भारत वर्ष 2006 में एक पर्यवेक्षक देश बन गया।
- * भारत वर्ष 2010 में FATF का 34वाँ सदस्य बना।
- * भारत इसके क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) और यूरोशियन ग्रुप (EAG) का भी सदस्य है।

FATF की सूचियाँ:

* ग्रे लिस्ट:

- ❖ इसका मतलब है- "बढ़ी हुई निगरानी सूची"
- ❖ इसमें आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माने जाने वाले देशों को शामिल किया जाता है।
- ❖ संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

* ब्लैक लिस्ट:

- * असहयोगी देश या क्षेत्र (Non-Cooperative Countries or Territories-NCCT) शामिल हैं ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
- * देश-इरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार

नबिर्ष

FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट अवैध वित्त के वरिद्ध संघर्ष में भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। **धन शोधन वरिधी और आतंकवाद वरिधी वित्तपोषण में अग्रणी के रूप में मान्यता अन्य देशों के लिये एक बेंचमार्क स्थापित करती है**, जबकि NPO और PEP जैसे क्षेत्रों में नरितर सुधार की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण बनी हुई है। यह मूल्यांकन भारत को भविष्य के आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये अनुकूल स्थिति में रखता है।

और पढ़ें: [भारत पर FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट](#)

???????? ???? ????:

प्रश्न: भारत की वित्तीय अखंडता हेतु FATF पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के महत्त्व और भारत पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

Q. चर्चा कीजिये किकिसि प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से नपिटने के लिये किये जाने वाले उपायों को वसितार से समझाइये। (2021)

